

इसे वेबसाइट www.govtprintmp.nic.in से
भी डाउन लोड किया जा सकता है।



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 314]

भोपाल, मंगलवार, दिनांक 19 जून 2018—ज्येष्ठ 29, शक 1940

गृह (सी-अनुभाग) विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 19 जून 2018

क्र. 2919-881-2018-दो-सी-1.—चूंकि, राज्य सरकार को यह समाधान हो गया है कि लोकहित में यह आवश्यक तथा समीचीन है कि नीचे दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट की गई सेवाओं में कार्य करने से इंकार किए जाने का प्रतिषेध किया जाए,

अतएव, मध्यप्रदेश अत्यावश्यक सेवा संधारण तथा विचिन्ता निवारण अधिनियम, 1979 (क्रमांक 10 सन् 1979) की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा दर्शावी अनुसूची में विनिर्दिष्ट अत्यावश्यक सेवाओं में कार्य करने से इंकार किए जाने का, दिनांक 19 जून 2018 से तीन माह की अवधि के लिए प्रतिषेध करती है:—

अनुसूची

उचित मूल्य की दुकानों की सार्वजनिक वितरण प्रणाली और खाद्यानों सहित अन्य आवश्यक वस्तुओं के सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन उर्पाजन के अंतर्गत सभी कार्यरत कर्मी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. आर. भोसले, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 19 जून 2018

क्र. 2919-881-2018-दो-सी-1.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 19 जून 2018 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. आर. भोसले, उपसचिव.

Bhopal, the 19th June 2018

F. No. 2919-881-2018-II-C-1.—WHEREAS, the State Government is satisfied that it is necessary and expedient in the public interest to Prohibit refusal to work in the essential services specified in the Schedule below;

THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 4 of the Madhya Pradesh Atyavashyak Sewa Sandharan Tatha Vichchinnata Nivaran Adhiniyam, 1979 (No. 10 of 1979), the State Government hereby prohibits refusal to work in the essential services specified in the Schedule with effect from 19th June 2018 for a period of three months:—

SCHEDULE

All Working staff in public distribution system of fair price shops and procurement under public distribution system of other essential commodities including food grains.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
R. R. BHONSLE, Dy. Secy.